

आजुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 26

लखनऊ, बुद्धवार 14 अक्टूबर 2026 सा 20 अक्टूबर 2026 तक

पृष्ठ—8

मूल्य : एक रुपया

विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

नई दिल्ली। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। एक दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। विपक्षी नेताओं के मार्च को



सुप्रीम कोर्ट से आधा किलोमीटर दूर रोक दिया गया। वहां से विपक्ष के चुनिंदा नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की। यह याचिका 90 विपक्षी राजनीतिक दलों के 99 नेताओं की ओर से दायर की गई है। इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया। जब विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो वहां राहुल गांधी की लीगल टीम पहले से मौजूद थी। लीगल टीम ने याचिका तैयार कर रखी थी, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने रविवार को चिट्ठी लिख कर चीफ जस्टिस से मिलने का समय मांगा था। विपक्ष उनको

ज्ञापन देना चाहता था। लेकिन चीफ जस्टिस ने मिलने का समय देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हितों के टकराव, शक्तियों के पृथक्करण और मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के हवाले मिलने का समय देने से इनकार किया था। इसके बाद

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का फैसला किया। राहुल ने इससे पहले एक प्रेस कन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मार्च शिवजी की बारात की तरह है, जिसमें जो चाहे वह शामिल हो सकता है। इसके बाद राहुल कांस्टीट्यूशन क्लब पहुंचे, जहां से विपक्ष ने मार्च शुरू किया। राहुल गांधी के मार्च में देरी होने पर उनकी कानूनी टीम ने दोपहर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के शाम साढ़े चार बजे बंद होने की समय सीमा के बाद याचिका दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है। आम तौर पर

ऐसे मामलों में पक्षकार सुप्रीम कोर्ट की ई फाइलिंग सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से सौगत राय, राजद से तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे की शिव सेना से संजय राउत, सीपीएम महासचिव एमए बेबी, सीपीआई महासचिव डी राजा, जेएमएम सांसद महुआ माझी, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले और मुस्लिम लीग से ईटी मोहम्मद बशीर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल सपा के नेता अखिलेश यादव ने कहा, 'आंदोलन और धरना जारी रहेगा। लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी, चुनाव आयोग के साथ मिलकर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वह हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है। वे फर्जी वोटर लिस्ट बनाते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और चुनाव के नतीजे तैयार करते हैं'। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'देश की जनता उन्हें नहीं भूलेगी। हम सभी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। अब उन्हें सजा देने का समय आ गया है'।

जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने का प्रयास कर रहे तीन सीजेपी नेता हिरासत में

लखनऊ। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को मंगलवार को कथित तौर पर जंतर-मंतर में प्रवेश करने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास

फहराया था। उन्होंने पूछा, "तिरंगा फहराना कब से उल्लंघन बन गया? उन्होंने यह पूछा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले उन लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। श्री दिपके ने पुलिस से



किया। पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी कि सुबह की इस घटना के दौरान पार्टी के कई सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। श्री दिपके ने जंतर-मंतर को एक प्रदर्शन स्थल के रूप में खत्म करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा आप प्रतिरोध को सूची से बाहर नहीं कर सकते। उन्होंने इस पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया। श्री दिपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी टीम ने जंतर-मंतर जाकर तिरंगा

यह भी आग्रह किया कि हिरासत में लिए गये सदस्यों को अपने वकीलों से परामर्श करने की अनुमति दी जाये। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खुद पहले 24 घंटे तक कानूनी परामर्श के बिना हिरासत में रखा गया था। उन्होंने कहा, "पूरा देश जंतर-मंतर बन जायेगा। जंतर-मंतर सिर्फ एक जगह नहीं है यह प्रतिरोध की एक भावना है।" उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को "तानाशाही मानसिकता" का उदाहरण बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को सीमित करने का प्रयास कर रही है।

२३ अक्टूबर को स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को मिलेगा अवकाश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं को 23 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मतदान के दिन पात्र मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश देने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की है। मुख्य निर्वाचन

अधिकारी के अनुसार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद शामिल हैं। शासन के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और संबंधित स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रमाणित मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस पर विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमत्य होगा। निर्वाचन अधिकारियों ने पात्र मतदाताओं से मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।

नए मतदाता बनने के लिए यूपी में 99 और 28 अक्टूबर को पंजीकरण के लिए लगेगे विशेष कैंप

लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों और पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के लिए 99 और 28 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। दोनों दिन प्रदेश के सभी जिलों के प्रत्येक मतदेय स्थल पर सुबह 90 बजे से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। कैंप में मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा

है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रत्येक बूथ पर कैंप आयोजित कराने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के



निर्देश दिए हैं। साथ ही पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे कैंप में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांचें। नाम नहीं होने पर पात्रता के अनुसार फार्म-6 भरकर पंजीकरण कराएं। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए

पात्र नागरिकों को फार्म-6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और पते से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां फार्म भरने और पंजीकरण की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। कैंप की जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी इसकी सूचना दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित निर्वाचन अधिकारी कैंपों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

सम्पादकीय

रुपये की गिरावट पर 'बैंड-एड' से कब तक चलेगा काम?

भारतीय रुपये की गिरती कीमत को थामने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से किए जा रहे प्रयास फिलहाल स्थायी समाधान की बजाय तात्कालिक राहत तक सीमित नजर आते हैं। पिछले महीने विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा (एफसीएनआर) योजना के तहत १२७ अरब डॉलर की राशि भारत आने से रुपये को कुछ समय के लिए सहारा मिला था। इससे ड लर के मुकाबले रुपये की गिरावट पर अस्थायी रोक भी लगी, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पिछले कुछ दिनों में रुपये पर फिर दबाव बढ़ने लगा है। इससे स्पष्ट है कि केवल विदेशी पूंजी जुटाकर मुद्रा की कमजोरी को लंबे समय तक दूर नहीं किया जा सकता। एफसीएनआर योजना के तहत जमा रकम की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर अगले तीन से पांच वर्षों में बड़ी मात्रा में ड लर देश से बाहर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार पर दोबारा दबाव पड़ने की आशंका रहेगी। इसलिए इस योजना से मिली राहत को रुपये की मजबूती का स्थायी आधार मानना उचित नहीं होगा। वास्तविक चुनौती रुपये की कीमत को त्रिम सहारे के बजाय आर्थिक बुनियाद पर मजबूत करने की है। रुपये की लगातार गिरावट को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने अब विदेशी मुद्रा बाजार में कई नियामकीय बदलाव किए हैं। डेरिवेटिव कारोबार और विदेशी मुद्रा लेन-देन पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। डॉलर में लेन-देन करने वाले संस्थानों के लिए न्यूनतम भंडार रखने की शर्तें लागू की गई हैं। तेल विपणन कंपनियों के कच्चे तेल के भुगतान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही, कंपनियों को डॉलर में भुगतान की स्थिति में अपने फ र्वर्ड क न्ट्रैक्ट रद्द न करने की हिदायत दी गई है। इन कदमों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग और आपूर्ति के असंतुलन को नियंत्रित करना तथा रुपये की गिरावट की रफ्तार को कम करना है। इससे पहले भी आरबीआई रुपये को संभालने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता रहा है। हालांकि, इस तरह के हस्तक्षेप से बाजार में अचानक आने वाले दबाव को कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। विदेशी मुद्रा भंडार असीमित नहीं है और उसे लगातार खर्च करके किसी मुद्रा की कीमत को लंबे समय तक एक स्तर पर बनाए रखना संभव नहीं है। इसी तरह, नियमों में बदलाव बाजार की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे रुपये की कमजोरी के मूल कारणों को अपने आप दूर नहीं कर सकते। रुपये पर दबाव के पीछे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के कारक काम कर रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड पर आकर्षक ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर अमेरिका में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इससे ड लर की मांग बढ़ती है और रुपये सहित अन्य मुद्राओं पर दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ईरान से जुड़ी युद्ध परिस्थितियों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम बढ़ जाता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है और डॉलर की मांग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उर्वरक, रसायन और अन्य जरूरी वस्तुओं की लागत में वृद्धि भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। रुपये की कमजोरी का असर केवल विदेशी मुद्रा बाजार तक सीमित नहीं रहता। इससे आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और उद्योगों की उत्पादन लागत पर दबाव पड़ सकता है। यदि इसका असर लंबे समय तक बना रहता है, तो आम उपभोक्ताओं की जेब से लेकर सरकार के वित्तीय प्रबंधन तक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि रुपये को संभालने के लिए तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान दिया जाए। निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाना, ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाना, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना और विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। साथ ही, विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ानी होगी। स्पष्ट है कि आरबीआई के हालिया कदम रुपये की गिरावट की रफ्तार कम करने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। आर्थिक चुनौतियों का जवाब केवल नियामकीय पाबंदियों और विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल में तलाशने के बजाय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती में खोजना होगा। आखिर, 'बैंड-एड' घाव को कुछ समय के लिए ढक सकता है, उसका स्थायी इलाज नहीं कर सकता।

योगी सरकार ने ६.१८ लाख किसानों को भेजे ४६३ करोड़ रुपये, आपदा प्रभावितों को भी मिलेगी राहत

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ४६३ करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि जारी की। गोरखपुर

रुपये की सहायता स्वीत हुई है, तो उसके खाते में पूरी रकम पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत १.२० लाख रुपये



में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के ६,१८,०६१ किसानों के बैंक खातों में यह धनराशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर जनहानि और पशुहानि भी हुई है। सरकार ने ८ से १० दिन के भीतर प्रभावित किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बरसात के दौरान अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग १,००० करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य संकट की घड़ी में अन्नदाता किसानों और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल क्र प सर्वे के आधार पर जिन जिलों की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, वहां प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई है। पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका न रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को २५ हजार

की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह राशि ४६३ करोड़ रुपये की फसल क्षति सहायता से अलग है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह बह गए या नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल आवास उपलब्ध कराया जाए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। पशुहानि के मामलों में भी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं, जनहानि होने पर संबंधित परिवार को २४ घंटे के भीतर चार लाख रुपये की सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारी सहायता का पूरा पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार की ओर से भेजे गए १०० रुपये में से केवल १५ रुपये ही जरूरतमंद तक पहुंचते हैं। योगी ने आरोप लगाया कि पहले बिचौलियों के कारण लाभार्थियों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से दी जाने वाली सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचती है। उन्होंने २०१७ से पहले

की सपा सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि उस समय बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिल जरूर आता था। अब किसानों को बिजली मिल रही है और उन्हें बिल से राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने वर्ष २०१४ में आए हदहद चक्रवात का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उस दौरान केंद्र सरकार की ओर से ३,२०० करोड़ रुपये भेजे गए थे, लेकिन किसानों तक केवल ८०० करोड़ रुपये ही पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि वर्ष २०१७ में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इस मामले की जांच कराई गई, तो पता चला कि पूरी सहायता राशि किसानों तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की गई। योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने किसानों का पैसा खाया और किसानों का श्राप उसे ले डूबा। उन्होंने विपक्ष पर समाज को जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता के पैसे को पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से कटान वाले क्षेत्रों और अतिवृष्टि की शिकायत वाले इलाकों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कराए जाएं। बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए और बारिश से क्षतिग्रस्त मार्गों को जल्द दुरुस्त कर आवागमन बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा, अतिवृष्टि या चक्रवात से सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सिंचाई विभाग को कटान रोकने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), नगर विकास विभाग, आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों को भी मरम्मत कार्यों के लिए धन दिया गया है। मौसम साफ होते ही काम शुरू कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

अज्ञात वाहन की टक्कर से मां-बेटा गंभीर घायल, चालक फरार

रायबरेली। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में रतापुर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गायत्रीपुरम निवासी सिमरन सेन पुत्री महेंद्र सेन ने पुलिस को दी

गई तहरीर में बताया कि चार अक्टूबर २०२६ की रात करीब ६२० बजे उनका भाई अपनी मां जमुना सेन को बाइक से दवा दिलाने के लिए रतापुर चौराहे की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और मां-बेटा

गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिल एरिया थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मिशन शक्ति की मिसाल बनीं छात्राएं: शगुन पाल बनीं एक दिन की प्रधानाचार्या, पलक ने संभाली उप प्रधानाचार्या की जिम्मेदारी

लखनऊ। बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा, विकास क्षेत्र नगर जोन-एक में मिशन शक्ति के तहत एक प्रेरणादायक पहल की गई। इस दौरान कक्षा सात की दिव्यांग छात्रा शगुन पाल को एक दिन की प्रधानाचार्या तथा कक्षा आठ की छात्रा पलक को एक दिन की उप प्रधानाचार्या की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पहल ने न केवल बालिकाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि अवसर मिलने पर बेटियां नेतृत्व की हर जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती हैं। एक दिन की प्रधानाचार्या बनीं शगुन पाल और उप प्रधानाचार्या पलक ने विद्यालय के दैनिक कार्यों का नेतृत्व करते हुए अपनी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया। दोनों

छात्राओं ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की, कक्षाओं का निरीक्षण किया, विद्यार्थियों की



समस्याएं सुनीं तथा विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उनके नेतृत्व में विद्यालय में अनुशासन, स्वच्छता और शैक्षिक गतिविधियों को लेकर सकारात्मक वातावरण देखने को मिला।

विद्यालय की जिम्मेदारियों को करीब से समझने और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी करने का यह

अनुभव छात्राओं के लिए बेहद खास रहा। कक्षा सात की दिव्यांग छात्रा शगुन पाल को प्रधानाचार्या की जिम्मेदारी सौंपना इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। इस पहल ने संदेश दिया कि प्रतिभा, इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता

किसी शारीरिक चुनौती की मोहताज नहीं होती। समान अवसर और उचित प्रोत्साहन मिलने पर प्रत्येक छात्रा अपनी क्षमताओं को पहचानकर आगे बढ़ सकती है। इस अवसर पर छात्राओं ने विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी निभाने पर खुशी और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने मिशन शक्ति के संदेश को आगे बढ़ाने तथा बालिकाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने का संकल्प भी व्यक्त किया। विद्यालय प्रशासन के अनुसार, मिशन शक्ति के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियों का उद्देश्य बालिकाओं को नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराना, उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना है। ऐसे कार्यक्रम छात्राओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के साथ-साथ समाज में उनकी

सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पाण्डेय ने शगुन पाल और पलक को बधाई देते हुए कहा कि मिशन शक्ति के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे अन्य छात्राओं को भी प्रेरणा मिलेगी और वे अपने भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को पहचानकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगी। कार्यक्रम ने विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सकारात्मक संदेश दिया। बेटियों को जिम्मेदारी, सम्मान और समान अवसर देकर ही सशक्त समाज की नींव रखी जा सकती है। बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा की यह पहल इसी सोच को मजबूती प्रदान करती है कि आज की जागरूक और आत्मविश्वासी छात्राएं ही कल के सशक्त नेतृत्व की आधारशिला बनेंगी।

लखनऊ में 996 शिक्षकों का सम्मान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया शैक्षिक संगोष्ठी का शुभारंभ

लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। निपुण भारत मिशन और वंदे

मातरम पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने हरदोई की राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका मंजू वर्मा सहित प्रदेश के 996 शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों को विद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों, निपुण भारत मिशन की प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर

कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अतिथियों ने शिक्षकों को अंगवस्त्र, स्मृति चिह्न और अभिनंदन पत्र प्रदान किए। राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने शिक्षण संवर्धन से जुड़े विभिन्न



विषयों पर अपने विचार रखे। वहीं, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य प्रमिला गुप्ता ने बच्चों से जुड़े मुद्दों पर विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के संयोजक मनीष देव, अयोध्या ने बताया कि इस अवसर पर शिक्षकों की नौ सूत्रीय मांगों

का ज्ञापन उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के प्रतिनिधि विनीत शर्मा को सौंपा गया। समारोह में पंकज कुमार वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय कुमार भुर्जी, आनंद द्विवेदी (लखनऊ) और विजय सोनी (कानपुर) सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजन में पंकज कुमार वर्मा, बिंबिसार बौद्ध, अजय कुमार पांडे, कुंवरपाल गौतम, ओमवीर सिंह, विकास त्रिपाठी, मयंक गुप्ता और सेविना दीक्षित सहित शिक्षकों ने विशेष सहयोग प्रदान किया।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत, दो गंभीर

रायबरेली। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। राही गांव निवासी अरविंद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में

बताया कि १२ अक्टूबर की शाम करीब ७:१३ बजे उनका भाई अजय कुमार (२५) अपने मित्र रंजीत और रिश्तेदार सुरेंद्र के साथ बाइक से राही से रायबरेली की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में राख और सीमेंट ढोने वाले एक अज्ञात ट्रक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर

पहुंची एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने अजय कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि रंजीत और सुरेंद्र का उपचार जारी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिल एरिया थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि अरविंद कुमार की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

फर्जी वसीयत के जरिए बेशकीमती जमीन अपने नाम कराने वाली पुष्पा देवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। के बख्शी का तालाब क्षेत्र के सैरपुर थाना अंतर्गत बौरूमऊ गांव में फर्जी वसीयत के जरिए बेशकीमती जमीन अपने नाम कराने वाली पुष्पा देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला चार दशक से भी ज्यादा पुराना है, जिसमें चकबंदी अदालतों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद जगी है। शिकायतकर्ता पुत्तिलाल के

करा ली। पुत्तिलाल ने इस जालसाजी के खिलाफ चकबंदी न्यायालय में मोर्चा खोला। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, लखनऊ ने २३ दिसंबर २०२४ को पुष्पा देवी का नाम खारिज कर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद, उपसंचालक चकबंदी, लखनऊ ने भी चार फरवरी २०२६ को पीड़ित पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया। जमीन गंवाने के



अनुसार, उनके नाना साधू के नाम बौरूमऊ गांव में जमीन दर्ज थी। साधू के निधन के बाद वर्ष १९७७ में उनकी दो बेटियों (चंद्रावती और रूपाना) के नाम एक खाते की जमीन दर्ज हो गई थी, लेकिन दूसरे खाते में नाम नहीं चढ़ पाया था। इसी बात का फायदा उठाकर पुष्पा देवी ने अपने पति किशोरी लाल द्विवेदी और अन्य साथियों के साथ मिलकर ३० जून १९८१ को साधू के नाम से एक फर्जी वसीयत तैयार करवा ली और चुपचाप जमीन अपने नाम दर्ज

डर से आरोपियों ने पुत्तिलाल को जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। स्थानीय थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने पुलिस आयुक्त कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सैरपुर थाने में ३ सितंबर २०२६ को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी पुष्पा देवी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कोरी ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही है।

एक दिन लगे या दो साल, पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा: राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा और इसमें चाहे एक दिन लगे या दो साल, वह पीछे नहीं हटेंगे। श्री गांधी ने मंगलवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आंदोलन को लेकर उनकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने में कल, परसों, तीन महीने, छह महीने, एक साल या दो साल लग सकते हैं, लेकिन वह उसी ऊर्जा, ताकत और एकजुटता के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। उनका कहना था कि उनकी इस लड़ाई में पूरा विपक्ष एकजुट है और सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मंगलवार को अपने आवास पर इंडिया गठबंधन

के नेताओं को चाय पर बुलाने के दौरान आगे के आंदोलन की रणनीति पर विचार-विमर्श के बाद कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को खत्म करने की अपनी मांग पर उन्होंने कहा कि मांग पूरा होने तक वह रुकेंगे नहीं। उनकी मांगें पूरी होने में चाहे कल, परसों, तीन महीने, छह महीने, एक साल या दो साल लग जाएं, संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस ऊर्जा, ताकत और एकजुटता के साथ पिछले कुछ दिनों में सभी दलों ने काम किया है उसी भावना के साथ आगे भी मिलकर लड़ाई जारी रखेंगे और लोकतंत्र की बहाली के अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह अलग-अलग या समानांतर विरोध प्रदर्शन नहीं हैं बल्कि एक ही

आंदोलन है जिसका एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र को बहाल करना है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है, चुनाव व्यवस्था को कमजोर किया गया है और संविधान को तार-तार कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन



देश में वास्तविक लोकतांत्रिक शासन की बहाली के लिए मिलकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का एक मंच था लेकिन सरकार ने अब वहां विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। विपक्ष इस फैसले को चुनौती देगा। श्री गांधी ने कहा कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि भारतीय

जनता अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार, गृह मंत्री अमित शाह को इसे लागू करने वाला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित अन्य लोगों को इसमें शामिल बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि अब उनके चारों ओर शिकंजा कस रहा है। भारतीय संविधान को नष्ट करके वे बच नहीं सकते। उनका कहना था कि सोमवार को दिल्ली में लोगों ने केवल राजनीतिक दलों को एकजुट होकर खड़े नहीं देखा बल्कि यह भारत की जनता की आवाज थी। उन्होंने दिल्ली और देश के लोगों का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह लड़ाई विपक्षी दलों के बारे में नहीं बल्कि भारत की जनता और उसके भविष्य के बारे में है। श्री गांधी ने कहा कि जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है कि लोकतांत्रिक

प्रक्रिया बहाल करने के लिए वे अंत तक लड़ेंगे और इस मामले में जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी, श्री शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और छिपी बैठी एक महिला सहित अन्य कई लोग शामिल हैं। श्री गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका की इस मामले में अहम भूमिका है और उन्हें उम्मीद है कि वह अपनी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल इसके लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। श्री गांधी ने कहा कि इस लड़ाई में कोई भी परिस्थिति बने या कोई संस्था अपनी भूमिका निभाए अथवा नहीं, उनका राजनीतिक प्रतिरोध और जनता का प्रतिरोध जारी रहेगा और अंततः इसकी जीत होगी।

सीजेपी ने २४ घंटे का अल्टीमेटम दिया

नई दिल्ली। कॉंग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोमवार को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। सीजेपी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे पहले सीजेपी ने २० जून से २५ जुलाई तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। अब सीजेपी ने दिल्ली पुलिस को २४ घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उसने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तारीख नहीं मिली तो

फिर आंदोलन करेंगे। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास सोमवार को प्रदर्शन की अनुमति मांगने पार्लियामेंट



स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। रांका ने कहा कि संगठन ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस को चिट्ठी देकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। उन्होंने पुलिस को प्रदर्शन की तारीख तय करने का अ प्शन भी

दिया है। रांका ने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि कोई वहां नहीं था। उन्होंने तंज करने के अंदाज में कहा, 'ऐसा लग रहा था कि सीजेपी के पहुंचने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को खाली करा दिया गया है'। इसी बीच, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने हिरासत का वीडियो एडिट करके जारी किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में वकील से संपर्क करना कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। दीपके ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

जंतर मंतर पर अब नहीं हो सकेगा प्रदर्शन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों की सूची से हटा दिया है। सोमवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। कोई पार्टी या संगठन वहां प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं मांग सकता है। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने इस बारे में विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर इसे प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों की सूची से हटाया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ३३ साल पहले जंतर मंतर को प्रदर्शन की जगह तय किया था। हालांकि उसके बाद भी एक बार वहां रहने वाले लोगों की अपील पर वहां प्रदर्शन बंद कराया गया था। लेकिन बाद में फिर से प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिश पर

जंतर मंतर को हटा दिया गया और रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल बनाया गया। बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शन और धरना



आयोजित करने के लिए वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने के मकसद से एक कमेटी बनाई थी। इसकी सिफारिशों के बाद रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड नाम तय किए। अभी यहां के लिए एसओपी जारी नहीं की गई है। पहले की एसओपी के मुताबिक रामलीला मैदान में ५० हजार तक लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। बुराड़ी ग्राउंड की क्षमता ५० हजार से ज्यादा लोगों की है।

ट्रंप ने जेलेंस्की पर शांति समझौते के लिए दबाव बढ़ाया

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर रुस के साथ समझौता करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फिलहाल राष्ट्रपति जेलेंस्की की तुलना में समझौता करने में अधिक रुचि है। श्री ट्रंप ने पत्रकारों से कहा श्री जेलेंस्की को समझौता करने पर ध्यान देना चाहिए न कि उस बारे में बात करने पर। हमें श्री जेलेंस्की को समझौता करने के लिए तैयार करना होगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों पक्षों की सीधी तुलना करते हुए कहा मुझे लगता है कि वास्तव में पुतिन, जेलेंस्की

की तुलना में समझौता करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। श्री ट्रंप ने रुस से डीजल आपूर्ति के संदर्भ में हुए अपने हालिया समझौते का बचाव किया। उन्होंने कुछ



रिपब्लिकन नेताओं की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि रुसी ईंधन के निर्यात पर रोक लगाने से वैश्विक बाजार को नुकसान होगा। श्री ट्रंप ने कहा

यह वास्तव में मेरे लिए कोई समझौता नहीं है बल्कि यह बाकी दुनिया के लिए एक समझौता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया कि डीजल की आपूर्ति सीमित करने से अंतरराष्ट्रीय ईंधन बाजार पर बहुत असर पड़ेगा और उन्होंने कहा कि वह ऐसे उपायों का समर्थन करते हैं जिनसे अमेरिकी किसानों और पशुपालकों को मदद मिल सके। राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका यूक्रेन पर रुस के साथ बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव बढ़ा रहा है और साथ ही डीजल समझौते के माध्यम से रुस के साथ ऊर्जा सहयोग भी बढ़ा रहा है।

पाकिस्तान में ट्रेन पटरी से उतरी चार यात्रियों की मौत, 30 घायल

पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के शेर शाह में एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतरने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और ३० लोग घायल हो गए। स्पुतनिक ने यह जानकारी दी। यह दुर्घटना मंगलवार तड़के हुई जब ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी और पटरी से उतर गई। बचाव कर्मियों ने ट्रेन की १४ बोगियों से चारों शव बरामद किए और घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही।



राहुल का दावा, ज्ञानेश मैसेज करते हैं

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उनको मैसेज करते हैं और कई बार उनसे बात करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं राहुल ने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार अपराधी नहीं हैं। राहुल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार अपराध नहीं हैं, उनसे सारे काम करवाए जाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल ने ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बनने की सलाह दी थी। राहुल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने से एक प्रेस कन्फ्रेंस की, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि, आप लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं, आप सीधा ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हैं। क्या कभी उन्होंने आप से बात करने की कोशिश की? इस सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, 'हां उनके मैसेज आते हैं। ज्ञानेश कुमार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस

देख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आप अपराधी नहीं हैं, आपसे बस करवाया गया है। सबसे आसान रास्ता है कि इस्तीफा दो और रास्ते से हट जाओ। राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'दिल्ली को जेल बना



दिया गया है। ये पुलिस वाले डिस्टर्ब हैं। ये कह रहे हैं कि हमसे युवाओं को क्यों पिटवाया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि युवाओं को रोकने को कहा जा रहा है। आरएसएस के गुंडे महिलाओं को मार रहे हैं। एक तरफ हमसे कहा जा रहा है कि पैलेट गन चलाइए। राहुल ने आगे कहा, 'एक दिन हमें पुलिस ने रोका, जंतर मंतर पर पुलिस ने रोका, आज भी रोकेंगे। आपको लगता है कि क्या एक

दिन की बात है। ये मत सोचिए कि पांच दिन पहले शुरू हुआ था। सालों से हमें रोका जा रहा है, अब दिख रहा है। केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, 'आप सोच रहे हो कि हमारे लिए मुश्किल है। पुलिस हमें मार रही है। जितना आप थक रहे हो, उतना पुलिस थक रही है। पुलिस कह रही है कि हम ज्ञानेश कुमार को क्यों बचा रहे हैं। पेशेंस और पर्सिवरेंस, लगे रहना है। हम करेंगे, वे रोकेंगे, हमें लगे रहना है। जितने दिन लंगेंगे, एक महीने, दो महीने, साल हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने आगे कहा, 'ये हिंदुस्तान की जनता की इन्फॉर्ट्स हैं। देश के हर युवा से कह रहा हूं कि ये आपके फ्यूचर, आपकी इज्जत की लड़ाई है। अगर आप नहीं आ सकते तो शाम को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे, तब हमें स लिडेरिटी दिखाइए। जिस भी तरीके से ये कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन करिए। बताइए कि जो हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं होने देंगे।

लगातार तीसरे दिन अंबानी पर मस्क का निशाना

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इल न मस्क ने भारत के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के ऊपर लगातार तीसरे दिन निशाना साधा। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी स्टारलिनक को भारत में इंटरनेट सेवा देने का लाइसेंस मिल जाएगा तो इससे मुकेश अंबानी की कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेटलाइट के जरिए मिलने वाली स्टारलिनक की इंटरनेट सेवा की कीमतें भारत में काफी सस्ती होंगी। भारत में मस्क की कंपनी की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच मस्क ने कहा कि मार्केट में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से आखिरी फायदा भारतीय उपयोक्ताओं को ही होगा।

उन्होंने कहा कि स्टारलिनक के आने से अंबानी का मुनाफा थोड़ा घट सकता है, लेकिन उनका कारोबार बंद नहीं होगा। गौरतलब है कि जब से मुकेश अंबानी के साथ उनका



विवाद सार्वजनिक हुआ तब से यह बताया जा रहा है कि स्टारलिनक की सर्विसेज बहुत महंगी हैं और भारत में लोग कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। गौरतलब है कि अपनी कंपनी को लाइसेंस

मिलने में हो रही देरी के लिए मस्क रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जिम्मेदारी बता रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हाल ही में मस्क ने अपने एक पोस्ट में मुकेश अंबानी पर तंज कसते हुए उन्हें 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' लिखा था। इससे पहले एक पोस्ट में उन्होंने अंबानी को भारत का रियल बस बताया था। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा कि स्टारलिनक भारत के बिना इंटरनेट वाले इलाकों में कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है। इससे दूरदराज के वंचित बच्चों को शिक्षा और छोटे कारोबारियों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मिलेगी।

मास्को का ग्लोबल डिजिटल फोरम हुआ संपन्न

नई दिल्ली। रूस के उप-विदेश मंत्री अलेक्जेंडर अलीमोव ने कहा है कि मास्को में आयोजित दूसरे ग्लोबल डिजिटल फोरम में 900 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय डिजिटल एजेंडा के अहम मुद्दों पर खुली चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। श्री अलीमोव ने कहा



पिछले साल की तरह ही, ग्लोबल डिजिटल फोरम में लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। इसमें 900 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें संचार एवं डिजिटल विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, निजी कंपनियां और विशेषज्ञ लोग शामिल थे। राजनयिक के अनुसार, इस कार्यक्रम ने अंतरराष्ट्रीय डिजिटल मुद्दों, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा भी शामिल है, पर खुलकर एवं विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला। साथ ही, इसने प्रतिभागियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने वाले उपायों की पहचान करने में भी मदद की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस फोरम के माध्यम से 'वैश्विक दक्षिण' के देशों में रूस के विकसित तकनीकी समाधानों के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ी है, उनके अनुसार, इससे मास्को के साझेदारों को ज्यादा डिजिटल संप्रभुता प्राप्त

करने में मदद मिल सकती है। श्री अलीमोव ने कहा ऐसे घरेलू समाधानों को बढ़ावा देना तब और भी जरूरी हो जाता है जब कुछ बेईमान अंतरराष्ट्रीय पक्ष 'विकास में सहयोग' का दिखावा कर अपनी बिना परखी एवं अक्सर असुरक्षित तकनीकों को जबरदस्ती थोपने

की आक्रामक कोशिशें कर रहे हों। राजनयिक ने कहा कि फोरम में हुई बातचीत से अंतरराष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र में रूस और विकासशील देशों के बीच साझा रुख की पुष्टि हुई और साथ ही सहयोग के नए संभावित क्षेत्रों की भी पहचान की गई। श्री अलीमोव के अनुसार, प्रतिभागियों ने बार-बार साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के महत्व पर बल दिया, जिसकी बातचीत की प्रक्रिया रूस की पहल पर शुरू की गई थी। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा यह अंतरराष्ट्रीय संधि, जिस पर पहले ही ६४ देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए गैर-कानूनी कामों में सूचना एवं संचार तकनीकों के इस्तेमाल से निपटने का एक असरदार माध्यम बनेगी। दूसरे ग्लोबल डिजिटल फोरम का आयोजन आठ से १० अक्टूबर तक मास्को में किया गया।

जंग का मैदान बनी दिल्ली

नई दिल्ली। शनिवार को दिन भर लगभग पूरी दिल्ली जंग का मैदान बनी रही। क करोच जनता पार्टी ने सेंट्रल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरी दिल्ली को कब्जे में ले रखा था। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ३८ हजार जवान अलग अलग जगहों पर तैनात थे, जिन्होंने सात हजार के करीब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी और जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे युवाओं व छात्रों को अलग अलग जगहों से पकड़ा। उनको बसों में भर कर दूरदराज के इलाकों में ले जाया गया। देर शाम प्रदर्शनकारियों

को रिहा किया गया। इससे पहले सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि अगर प्रदर्शनकारी रिहा नहीं होते हैं तो वे आंदोलन करेंगे। इस बीच शनिवार की शाम को सीजेपी ने रविवार को फिर से जंतर मंतर की ओर मार्च करने का ऐलान किया। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर क करोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और वामपंथी पार्टियों के साथ साथ सिविल सोसायटी के लोगों ने १० अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरा जोर लगा कर प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर

पहुंचने से रोक दिया। जंतर मंतर पहुंचने का प्रयास करते हुए ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया गया तो अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में



दोनों को छोड़ दिया गया। सुबह की उड़ान से दिल्ली पहुंचे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अन्य नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया।

बाद में उनकी दादी के निधन की खबर आई तो पुलिस ने उनको घर जाने की इजाजत दे दी। असल में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जंतर मंतर के आसपास पांच लेयर की बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शन के लिए तय जगह तक पुलिस ने किसी को पहुंचने नहीं दिया। दीपके की गिरफ्तारी के बाद उनका एक पुराना वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको हिरासत में लिए जाने के बाद आजिंक्य शिंदे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। बाद में शिंदे ने कमान संभाली और लोगों से जंतर मंतर की ओर बढ़ने का आह्वान किया। सीजेपी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी की थी। आठ से १२ अक्टूबर तक के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की २२१ कंपनियां यानी करीब २३ हजार जवान दिल्ली बुला कर तैनात किए गए। इनके अलावा दिल्ली पुलिस के कम से कम १५ हजार जवानों और अधिकारियों की तैनाती की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए ४५ मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। करीब ढाई सौ ट्रेनें रद्द कर दी गईं। कनॉट प्लेस के आसपास दुकानें बंद थीं तो जंतर मंतर के चार किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद रखा गया था। स्कूल व कॉलेज भी या तो बंद थे या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी।

चीफ जस्टिस की इनकार वाली चिट्ठी सामने आई

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष की ओर से मिलने का समय मांगने की चिट्ठी के जवाब में जो चिट्ठी लिखी थी, वह कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। हालांकि इससे पहले सुबह में चीफ जस्टिस ने इसके कंटेंट के बारे में बताने से मना कर दिया था और कहा था कि पत्रकारों को विपक्ष से पूछना चाहिए। इस चिट्ठी में चीफ जस्टिस ने कहा कि एसआईआर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अदालत में विचाराधीन है इसलिए उनका विपक्षी नेताओं से मिलना मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर कहा कि ये उनका मुद्दा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और कोई भी आम नागरिक या निर्वाचित जनप्रतिनिधि याचिका दाखिल कर

सकता है। विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों का जवाब दिया। इस बीच, उनकी वह चिट्ठी भी सामने आई, जो उन्होंने रविवार को 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं को मुलाकात से



इनकार करने के लिए लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, वे पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में इन पर मीटिंग करना न्यायिक मर्यादा और नैतिकता के खिलाफ होगा। चीफ जस्टिस ने

लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को इन मुद्दों पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। लंबित मामलों पर विचार करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनानी होगी। चीफ जस्टिस ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 32 और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अगर सोमवार को याचिका दाखिल करे तो उसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक कानून में तय प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले: न्यायमूर्ति सूर्यकांत

नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया गठबंधन के सांसदों से मुलाकात करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा है कि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और हर भारतीय नागरिक को न्यायालय का रुख करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पत्रकारों से कहा कि किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित निकाय के सदस्य की याचिका का स्वागत किया जाएगा और कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें रविवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से मुलाकात का अनुरोध करते हुए पत्र मिला था। उन्होंने कल पत्र का जवाब देते हुए मुलाकात नहीं कर पाने का कारण भी स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से उन्होंने नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात करने में असमर्थता जताई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि किसी

भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने के लिए शीर्ष अदालत आने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष आने वाली याचिकाओं पर कानून के मुताबिक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि



न्यायपालिका सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है और किसी भी वैध याचिका पर उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी आम नागरिक या चुने हुए निकाय के सदस्य की याचिका का स्वागत है। हर भारतीय नागरिक को अदालत जाने का अधिकार है और हम उनकी बात सुनेंगे तथा कानून के तहत जो भी उचित होगा, वह करेंगे।

दिल्ली, एनसीआर में बारिश, ठंड ने दी दस्तक

नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में सोमवार की सुबह तेज बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली और एनसीआर में इस बारिश के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से आने वाले मौसमी सिस्टम के कारण बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक, पाकिस्तान

के ऊपर बना सिस्टम भारत में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश तक फैला है। बहरहाल, सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और अलीगढ़ सहित पांच शहरों में बारिश हुई। लखनऊ में लगातार 95वें दिन भी बाढ़ का असर है। इससे 80 हजार से ज्यादा घर प्रभावित हैं। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर,

चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश हुई। इससे मौसम ठंडा हो गया। उत्तराखंड के केंदारनाथ और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को बारिश, बर्फबारी हुई। नैनीताल में भारी ओले गिरे। हिमाचल प्रदेश के मनाली, चंबा और लाहौल स्पीति में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। इससे पारा गिरा और ठंड बढ़ी है।

लखनऊ में डॉक्टरों का फूटा गुस्सा, पुलिस बस के आगे लेटीं,

बोलीं- डिप्टी CM भूले वादा, 80 दिन से चल रहा धरना

लखनऊ। हजरतगंज में समान वेतन और बकाया एरियर की मांग को लेकर 80 दिन से प्रदर्शन कर रहे बॉन्डेड MBBS डॉक्टरों का गुस्सा मंगलवार को आखिरकार फूट पड़ा। पुलिस ने जब उन्हें जबरन उठाकर इको गार्डन भेजना

डटे हुए थे। पुलिस उन्हें वहां से हटाने के लिए बस लेकर पहुंची थी। विरोध जताते हुए कई महिला डॉक्टर बस के आगे लेट गईं और दो टूक कहा कि गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दो, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे। साथियों को हिरासत में

संस्थानों में दो साल की अनिवार्य बॉन्ड सेवा दे रहे हैं या इसके एवज में 90 लाख रुपए के बॉन्ड की बाध्यता झेल रहे हैं। इस कड़ी मेहनत के बदले उन्हें अभी सिर्फ 50 से 55 हजार रुपए महीना मानदेय मिल रहा है, जबकि उन्हीं की तरह समान डिग्री, समान बॉन्ड और चयन प्रक्रिया के तहत सेवा दे रहे दूसरे डॉक्टरों को 9.90 लाख रुपए प्रतिमाह तक वेतन मिल रहा है। डॉक्टर इसी भेदभाव को खत्म कर समान वेतनमान और बकाया एरियर का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने याद दिलाया कि बीते 2 सितंबर को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बारिश के बीच खुद हजरतगंज गांधी प्रतिमा पहुंचे थे। उन्होंने डक्टरों से करीब 20 मिनट तक बातचीत की थी और कहा था कि पत्रावली पूरी हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने अगले दिन दोपहर 2 बजे तक शासनादेश जारी करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उस समय प्रदर्शन रोक दिया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब कोई शासनादेश नहीं आया, तो डक्टरों का गुस्सा एक बार



चाहा, तो महिला डॉक्टरों ने पुलिस बस को हाथों से धक्का देकर रोक लिया और उसके आगे लेट गईं। डॉक्टरों का साफ कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे नहीं हटेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 2017, 2018 और 2020 बैच के बॉन्डेड MBBS डॉक्टर अपनी जायज मांगों को लेकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर

लिए जाने के विरोध में डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वे पिछले 80 दिनों से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के सीएचसी, पीएचसी समेत अन्य सरकारी स्वास्थ्य

खुदरा महंगाई लगातार 99वें महीने बढ़ी

नई दिल्ली। खुदरा महंगाई की दर में सितंबर के महीने में भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार 99वें महीने खुदरा महंगाई की दर बढ़ी है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में खुदरा महंगाई दर में 0.02 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में खुदरा महंगाई की दर 8.22 फीसदी थी, जो सितंबर में बढ़ कर 8.24 फीसदी पहुंच गई। सब्जियों और खाने पीने की अन्य चीजों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से खुदरा महंगाई की दर बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजों की महंगाई 5.67 से बढ़कर 6.08 फीसदी हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक शहरी महंगाई 8.39 से बढ़कर 8.41 हो गई है, जबकि गांवों की महंगाई दर 5.28 से

बढ़कर 6.08 फीसदी पर पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव से आपूर्ति शृंखला प्रभावित होने का असर हर चीज की कीमत पर पड़ा है। इस वजह से महंगाई लगातार 99वें महीने बढ़ी है। गौरतलब है कि महंगाई पर काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी महीने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 88 महीने के बाद आरबीआई ने पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना नहीं है। बैंक की आगे की नीति या तो ब्याज दरें बढ़ाने की होगी या फिर इन्हें इसी स्तर पर बरकरार रखा जाएगा।

मुंबई, पुणे, नासिक से सैकड़ों लोग पकड़े गए

मुंबई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का एपीसेंटर दिल्ली में था लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी खूब प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे और ज्ञानेश कुमार के ऊपर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा। मुंबई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के संगठन ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन कर रहे करीब चार सौ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये लोग दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में उतरे थे। हिरासत

में लिए गए लोगों में तुषार गांधी के संगठन 'हम भारत के लोग' के सदस्य और सीपीएम के कार्यकर्ता शामिल थे। उधर पुणे पुलिस ने 20 से एक सौ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें लश्कर पुलिस स्टेशन ले गई। बाद में छात्रों को रिहा कर दिया गया। नासिक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सीजेपी और कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की सांसद/विधायक अदालत २६ अक्टूबर को सुनाएगी फैसला

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की सांसद/विधायक अदालत ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला सुनाने के लिए २६ अक्टूबर की तिथि तय की। इस दिन राहुल गांधी को अदालत में आना पड़ेगा। वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिावक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज अदालत ने फैसले की तिथि २६ अक्टूबर तय की क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो चुकी है। पांडेय ने बताया कि प्रतिवादी (राहुल गांधी) पक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल की जा चुकी है, जिसमें अनुच्छेद १७ और १८ (मुख्यतः १८) में उन्होंने घटना और भाषण को स्वीकार किया है। बचाव

पक्ष ने धारा ४६६ (अपमानलेख्य मानहानि) के अपवाद उपबंध नौ का सहारा लेते हुए कहा है कि यह बयान सद्भावना की दृष्टि से दिया गया था और उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था। पांडेय



ने अदालत में कहा कि घटना स्वीकार किए जाने के बाद अब साबित करने का भार आरोपी पक्ष पर है। उन्होंने आरोप लगाया था कि बयान दूषित मानसिकता के साथ दिया गया था। उन्होंने अदालत से आरोपी को दोषी ठहराने

की मांग की। राहुल गांधी पर २०१८ में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त २०१८ को जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद अदालत में दायर किया था। अदालत ने २७ नवंबर २०२३ को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अदालत में हाजिर होकर जमानत कराई थी। इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी की आवाज के नमूने का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

निष्पक्ष चुनाव में माइक्रो प्रेक्षकों की भूमिका अहम : डीएम

लखीमपुर खीरी। उप्र विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन-२०२६ को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को अटल सभागार में माइक्रो प्रेक्षकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। माइक्रो प्रेक्षक मतदान केंद्रों पर सतर्कता से निगरानी रखें और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि माइक्रो प्रेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें मतदान केंद्र पर होने

वाली गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन करना होगा। उन्होंने सभी माइक्रो प्रेक्षकों से जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। सीडीओ योगानंद पाण्डेय ने प्रशिक्षण के दौरान माइक्रो प्रेक्षकों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। उन्हें मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति, प्रवेश पास व्यवस्था, मतदाताओं की पहचान, मतदान की गोपनीयता और वीडियोग्राफी संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए कहा गया। अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने

की जानकारी भी दी गई। दिव्यांग, निरक्षर एवं अशक्त मतदाताओं को दी जाने वाली सहायता और सहायकों की ओर से की जाने वाली घोषणाओं के नियमानुसार अनुपालन पर भी जोर दिया गया। मतदान अभिकर्ताओं के आचरण और उनकी शिकायतों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। पीडी (डीआरडीए) सतीश कुमार पाण्डेय ने कार्यशाला में स्पष्ट किया कि माइक्रो प्रेक्षक साधारण प्रेक्षक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। उनका मुख्य दायित्व मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करना और निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार करना है। प्रशिक्षण में आयोग के दिशा-निर्देशों, निर्धारित प्रपत्रों और रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

१५०० स्कूली बच्चों ने निकाली मां वैष्णो दरबार के दर्शन को पदयात्रा

गोला गोकर्णनाथ। नवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य कल्याण समिति के तत्वावधान में नगर के विभिन्न विद्यालयों के करीब १५०० विद्यार्थियों ने मां वैष्णो दरबार के दर्शन के लिए पदयात्रा निकाली। नगर पालिका परिषद परिसर से पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिकू ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और ऐसे धार्मिक आयोजनों से उनमें संस्कारों का विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास साफ-सफाई रखने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित

करने की अपील की। नगर पालिका परिषद से शुरू हुई पदयात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुरानी मिल क लोनी पहुंची। यहां पिछले करीब ३० वर्षों से सजाए जा रहे मां वैष्णो दरबार में विद्यार्थियों ने दर्शन किए। दरबार में निर्मित दुर्गम पहाड़ियों से गुजरते हुए बच्चों ने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पदयात्रा में इंडियन हेरिटेज एकेडमी, आदर्श दुर्गा विद्या मंदिर, पुरुषोत्तम बाल विद्या मंदिर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकेडमी, शारदे ज्ञान मंदिर, आदर्श सरस्वती बाल विद्या मंदिर, मां सरस्वती शिक्षा मंदिर, प्रकाश दीप शिक्षा निकेतन, इंडियन पब्लिक एकेडमी, सरस्वती ज्ञान मंदिर, अरविंद पब्लिक स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, आदर्श सरस्वती

विद्या मंदिर, माया मेमोरियल, यदुशील शिक्षा निकेतन, बजाज पब्लिक स्कूल और शारदे विद्या मंदिर के विद्यार्थी शामिल हुए। पदयात्रा का नेतृत्व पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिकू, विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य कल्याण समिति के प्रांतीय महामंत्री शैलेंद्र सक्सेना तथा मां वैष्णो दरबार के आयोजक अवधेश श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान समिति के कोषाध्यक्ष अनुज खरे, कार्यकारी अध्यक्ष डीपी श्रीवास्तव, मां दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, पूर्व मंडल अध्यक्ष कुंभी रविन्द्र कटियार, अतुल श्रीवास्तव, सुनील शर्मा, हिमांशु सिंह, अनूप अवस्थी, प्रदीप भगत, बबू सक्सेना, राजीव शुक्ला और संजय तिवारी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

ED ने जौहर यूनिवर्सिटी केस में रामपुर जेल जाकर आजम खान से मनी लॉन्ड्रिंग पर पूछताछ की

लखनऊ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने १३ अक्टूबर को रामपुर जिला जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से पूछताछ की। यह पूछताछ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई। म्व के लखनऊ जोनल अफिस की एक टीम दिन में रामपुर जेल पहुंची और एजेंसी की जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर पूछताछ की। यह पूछताछ उस बैरक में हुई जहाँ आजम खान अभी बंद हैं, और यह प्रक्रिया जारी रही। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए दूसरी जगह लगाने और बाद में उनके इस्तेमाल के आरोपों की जांच के तहत फेडरल एजेंसी ने उनका बयान दर्ज किया। इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी संपत्तियां बनाना भी शामिल है। यह घटनाक्रम करीब ढाई महीने पहले उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आजम खान से जुड़ी दस जगहों पर ED की छापेमारी के बाद हुआ है। ये अ परेशान १६ अगस्त को शुरू हुए थे और इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के साथ-साथ दिल्ली की जगहें भी शामिल थीं। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी शामिल थीं इस यूनिवर्सिटी की स्थापना आजम खान ने २००६ में की थी और यह रामपुर में स्थित

एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नक्शेदेखें म्व ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्ट के बीच पैसों का लेन-देन हुआ है और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा उठाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने फंड को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ दिया, जिसमें भारी डोनेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है। एजेंसी सरकारी फंड के कथित



गलत इस्तेमाल और हेरफेर से जुड़ी आपराधिक कमाई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूतों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। आजम खान २०१६ के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों (जिनमें तत्कालीन कलेक्टर- सह-जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल थे) के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए दो साल की सजा काट रहे हैं। रामपुर सदर से दस बार विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख मुस्लिम नेता रहे हैं। धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से वे पिछले साल नवंबर से रामपुर जिला जेल में बंद हैं।

ग्राम प्रहरियों को मानदेय वृद्धि और पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सौगात

लखीमपुर खीरी १३ अक्टूबर। गांवों में कानून-व्यवस्था की निगरानी और अपराध नियंत्रण में पुलिस के सहयोगी ग्राम प्रहरियों को मानदेय में बढ़ोतरी और पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा की सौगात दी गई है। मंगलवार को पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित जनपदीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। बड़ी संख्या में शामिल ग्राम प्रहरियों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम अंजनी कुमार सिंह और नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष ड . ईरा श्रीवास्तव ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय के साथ किया। इस दौरान सीओ सिटी महक शर्मा और सीओ मिताली यादवेन्द्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने ग्राम प्रहरियों को सरकार की ओर से घोषित

सुविधाओं के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराध नियंत्रण में पुलिस के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। उनकी सक्रियता से गांवों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी समय पर पुलिस तक पहुंचती है। उन्होंने ग्राम प्रहरियों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। नगर पालिकाध्यक्ष ड . ईरा श्रीवास्तव ने कहा कि ग्राम प्रहरी गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मानदेय में बढ़ोतरी और पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा से उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्राम प्रहरियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हुए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

लखनऊ के होटल की १०वीं मंजिल से गिरकर समरीन की मौत, साथ आया युवक फरारय हत्या की आशंका से जांच में जुटी पुलिस

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से एक दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ओमेक्स स्थित होटल सेलेस्टियल मैन्योर की १०वीं मंजिल से गिरकर २४ साल की समरीन की संदिग्ध



हालात में मौत हो गई। घटना के वक्त वह एक युवक के साथ होटल के कमरे में रुकी थी, जो लड़की के नीचे गिरते ही मौके से फरार हो गया। पुलिस और परिवार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, अंबेडकरनगर और सुल्तानपुर से जुड़े रहने वाले अवनीश जायसवाल उर्फ देव ने सोमवार दोपहर करीब १२ बजे होटल सेलेस्टियल मैन्योर में कमरा नंबर १०३७ बुक किया था। समरीन भी उसी के साथ होटल के अंदर गई थी। शाम करीब ६ बजे अचानक समरीन १०वीं मंजिल की बालकनी से नीचे आ गिरी। नीचे गिरते ही उसकी ब डी कई जगह से मुड़ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी युवक घबराकर भागा

और तुरंत लिफ्ट के रास्ते ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। इसके बाद वह पार्किंग से अपनी बाइक उठाकर वहां से रफूचक्कर हो गया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट को बुलाकर



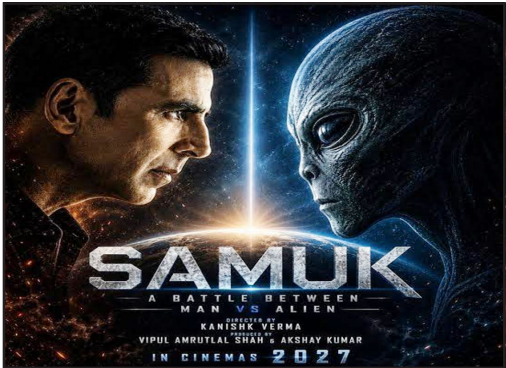
सबूत जुटाए। मृतका की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि आरोपी देव ने उनकी बेटी को धोखे से फंसाया और होटल ले जाकर १०वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। मेरी बेटी कपड़े लेने घर से निकली थी, लेकिन वह लड़का उसे बहला-फुसलाकर ले गया। होटल में उसने गलत नाम लिखवाया था। मेरी औलाद चली गई, मुझे इसाफ चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि समरीन बहुत सीधी-सादी थी और आरोपी कई महीनों से उसके संपर्क में था। परिवार को इस खौफनाक घटना की खबर देर रात मिली। परिवार की स्थितिरू समरीन पांच बहनों और दो भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। उसके पिता का

निधन सात साल पहले हो चुका है, जबकि उसके दोनों भाई विदेश में रहकर मेहनत-मजदूरी करते हैं। समरीन की शादी ६ साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद से वह अपनी मां और बहनों के साथ ही रह रही थी। उसका पति से तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को उसकी कोर्ट में पेशी भी थी, लेकिन वह घर से बहन के लिए कपड़े लाने की बात कहकर निकली थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अवनीश जायसवाल उर्फ गोलू मूल रूप से अंबेडकरनगर के अकबरपुर का रहने वाला है, जहां टांडा रोड पर उसके परिवार की श्रृंखला मशीनरी स्टोर्स के नाम से दुकान है। उसका ननिहाल सुल्तानपुर के दोस्तपुर में है, जहां उसका आना-जाना था। फिलहाल पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह मामला आत्महत्या का है, हादसा है या फिर सुनियोजित हत्या।



‘समुक’ में बनिता संधू की एंट्री!

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ‘समुक’ में अभिनेत्री बनिता संधू की एंट्री की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि निर्देशक कनिष्क वर्मा की इस साइंस-फिक्शन एक्शन और सर्वाइवल थ्रिलर में बनिता एक ब्रिटेन में जन्मी भारतीय पर्यावरणविद् की भूमिका निभा सकती हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बनिता का किरदार एक ऐसे मिशन का हिस्सा बन जाता है, जिससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए था। हालांकि, निर्माताओं की ओर से अभी तक उनके किरदार को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म के सह-निर्माता आशीष ए. शाह हैं। फिल्म की शूटिंग फिलहाल लंदन में चल रही है। ‘समुक’ के जरिए अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह करीब १३ साल बाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। बनिता संधू ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म ‘अक्टूबर’ से की थी। इसके बाद



वह ‘सरदार उधम’ और हालिया फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में नजर आई। वह अंतरराष्ट्रीय सीरीज ‘ब्रिजर्टन’ में भी काम कर चुकी हैं। हिंदी सिनेमा के साथ अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में काम करने का अनुभव रखने वाली बनिता की इस फिल्म में संभावित एंट्री से दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म में अक्षय कुमार और बनिता संधू के अलावा रुक्मिणी मैत्रा, विनीत कुमार सिंह, रजत कपूर और स्वानंद किरकिरे के भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने की खबरें हैं। हालांकि, कलाकारों के किरदारों और कहानी से जुड़े विवरणों को फिलहाल गोपनीय रखा गया है। फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर बना सस्पेंस दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। अब फिल्म की आधिकारिक घोषणा और इससे जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार है।

लखनऊ। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के आचारामऊ से मलाक जाने वाले कच्चे मार्ग पर सोमवार देर रात एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल



गई। शव के ठीक सिर के पास जूट का बोरा पड़ा मिलने से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बदमाशों ने युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को इस सुनसान रास्ते पर लाकर ठिकाने लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही बीकेटी पुलिस और फील्ड यूनिट फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए और इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, १२ अक्टूबर की रात करीब ११:३० बजे इस मार्ग पर शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद

उच्चाधिकारी भी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीसीपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मृतक की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक की मौत इसी जगह पर हुई या फिर वारदात को कहीं और अंजाम देकर शव यहां फेंका गया। पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल, पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

संजय बाजपेई

सीतापुर

मो.9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

सुरेश नारायण मिश्र

क्षेत्रीय सम्पादक

सौरभ कुमार, बिहार

मो.09386075289

मो० अरशद

ब्यूरो चीफ

मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई

UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email-

adbhutsamachar

@yahoo.in

adbhut_samachar

@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

‘सुमो दीदी’ का ट्रेलर जारी, २३ अक्टूबर को होगी रिलीज

मुम्बई। हिंदी जी५ ने भारत की पहली पेशेवर महिला सुमो पहलवान हेतल दवे के जीवन पर आधारित फिल्म ‘सुमो दीदी’ का ट्रेलर जारी कर दिया है। जयंत रोहतगी के निर्देशन में बनी इस



फिल्म में श्रीयम भगनानी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म २३ अक्टूबर को हिंदी जी५ पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में हेतल दवे के संघर्ष, दू संकल्प और सामाजिक रुढ़ियों को चुनौती देकर अपनी पहचान बनाने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में चौतन्य शर्मा, अनुभा फतेहपुरिया, नितेश पांडे, राघव धीर और मीनल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

जियो स्टूडियोज, फ्रेश लाइम फिल्म्स और मध्य एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के बैनर तले बनी इस फिल्म की शूटिंग जापान, कोलकाता और मुंबई में हुई है। यह फिल्म टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। निर्देशक जयंत रोहतगी ने कहा कि यह फिल्म केवल सुमो पहलवान बनने की कहानी नहीं, बल्कि अपनी पहचान और ताकत पर भरोसा करने तथा सामाजिक रुढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणादायक कहानी है। श्रीयम भगनानी ने कहा कि हेतल दवे का किरदार निभाना उनके लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा। वहीं, हेतल दवे ने उम्मीद जताई कि उनकी कहानी लोगों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक